भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3051
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2026

डाक संभार परिवर्तन

3051. डा. भागवत कराड़ :
श्री नरहरी अमीन :
श्री मयंककुमार नायक :
श्री अमर पाल मौर्य :
श्री तेजवीर सिंह :
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :
श्री बाबू राम निषाद :
श्री उज्जवल देवराव निकम :
श्रीमती माया नारोलिया :
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :
श्री घनश्याम तिवाड़ी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रूपरेखा के अंतर्गत डाक विभाग को एक बड़े पैमाने के सार्वजनिक संभार संगठन में बदलने के लिए किए जा रहे कौन-कौन से विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) बढ़ते हुए ई-कॉमर्स बाजार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग की पार्सल प्रहस्तन क्षमता में किस प्रकार संवृद्धि हुई है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष में अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नए प्रतिस्पर्धी डाक या पार्सल उत्पाद शुरू करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एमएसएमई निर्यात को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा डाकघरों की परिवर्तन रूपरेखा के कार्यान्वयन को कब तक पूरा करने का विचार रखता है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) डाक विभाग ने पार्सल वैल्यू चैन के कार्यप्रवाह को पुनः डिजाइन करने और दक्षता में सुधार लाने हेतु, मेल एंड पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमपीओपी) को कार्यान्वित किया है। इस पहल के भाग के रूप में, पार्सल नेटवर्क एवं डिलीवरी केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है और बढ़ते पार्सल और ई-कॉमर्स क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय सड़क परिवहन नेटवर्क को कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं की रियल टाइम ट्रैकिंग और सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए वर्ष 2025 में उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) प्लेटफॉर्म की शुरूआत की गई थी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य ग्राहकों के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण शुरू किया गया है। विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है और यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों को पार्सल डिलीवरी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों), कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और लघु व्यवसायों द्वारा किए जाने वाले निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए डाक निर्यात केंद्र (डीएनके) स्थापित किए गए हैं।

(ख) डाक विभाग की पार्सल हैंडल करने की क्षमता 2022-23 में 12.70 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14.57 करोड़ हो गई है।

(ग) एवं (घ) जी, हां। कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल (सीईपी) क्षेत्र में एक्सप्रेस सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने कतिपय चिह्नित घरेलू मार्गों पर '24 और 48 घंटे में गारंटीड डिलीवरी मेल' तथा '24-घंटे में डिलीवरी पार्सल' सेवाएं शुरू की हैं। विदेशों को भेजे जाने वाली ई-कॉमर्स सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा आरंभ की गई है।

(ङ) देशभर में भारतीय डाक को एक एकीकृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में रूपांतरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इन पहलों से घरेलू ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को मजबूती मिलने और बेहतर उत्पादों एवं उन्नत सेवा मानकों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

*****